(b) if so, what is the quantity of each imported during the last two years, yearwise;

(c) what are the names of the companies which imported the above drugs and what are the names of the countries from which these were imported;

(d) whether it is a fact that these drugs are produced in the country from basic stage;

(e) whether it is also a fact that production of these drugs are much higher than the total requirement of the country;

(f) whether it is a fact that Government have received a proposal to ban the imports of these drugs?

(g) if so, what are the details thereof and by when ban will be imposed on the imports of these drugs?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (c) Import of individual drugs is not being monitored by this Department.

(d) The stages of manufacture allowed for these drugs are given below:—

Metoprolol Tartarate—4 methoxy Ethyl Phenol

Albendazole—Meta-chloroaniline

Alprazolam—4-chloroquin

Fenbendazole—2-nitro-5-chloro aniline

(e) This Department monitors production of only some important bulk drugs and formulations.

(f) to (g) Representations have been received for shifting of one item namely, Albendazole from OGL to 3(a) of the EXIM Policy. The same has been examined and action taken, taking into consideration various factors such as demand, production, number of manufacturers, availability etc.

टिहरी बांध परियोजना की लागत

1521. श्री राम जेठमलानी: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध के निर्माण के लिये सरकार की वर्तमान निर्धारित लागत कितनी है ;

(ख) इस लागत के लिये क्या संसाधन तथा व्यवस्थाएं हैं ; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिये कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) टिहरी बांध परियोजना (टिहरी कामप्लैक्स का चरण-I) की अनुमानित लागत 1474 करोड़ रुपये है जबकि सम्पूर्ण टिहरी जल विद्युत कामप्लेक्स की लागत 3006.12 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) परियोजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है । परियोजना के वित्तपोषण के लिये इक्विटी वित्तीय भागीदारी क्रमशः 75:25 के अनुपात में है । किसी कमी की सम्पूर्ण लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जायेगी । प्रस्तावित सघ टिहरी जल विद्युत कामप्लेक्स के लिये 1000 मिलियन रुपये की तकनीकी और वित्तीय व्यवस्था देने के लिये सहमत हो गया है ।

(ग) टिहरी बांध चरण-I परियोजना के जून 1997 तक पूरी किये जाने की प्रत्याशा है ।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना

1522. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ उद्योगों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में स्थापित किए गए ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है और इसके साथ ही उन जगहों के नाम क्या हैं, जहां ये स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) इन उद्योगों में लगी पूरी पूंजी कितनी है और कितने लोगों को इनमें रोजगार दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्ष के दौरान पंजाब में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) 31-3-1989 तक पंजाब में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अक्त परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजीनिवेश 802.76 करोड़ रु. का था तथा उक्त तारीख तक कर्मचारियों की कुल संख्या 0.23 लाख थी।

Winding up of MRTP Commission

1523. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the M.R.T.P. Commission has since been rendered paralysed by Government by not appointing new incumbents against vacant posts due to the retirement of two of its three members and premature death of one member;

(b) whether Government are contemplating to wind up the said Commission; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) No, Sir. Action is under way to fill up the vacant posts.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

टिहरी बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था

1524. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार अवतार सिंह अरोड़ा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टिहरी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण के कारण कितने परिवार बेघर तथा बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास और पुनः रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री, राज्य में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सरकार ने नवम्बर, 1986 में टिहरी पन विद्युत परियोजना कमलेक (2,400 मेगावाट, जिसमें टिहरी बांध परियोजना शामिल है, को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में कार्यान्वित किए जाने और इसके लिए सांविधिक मंजूरी तथा वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने का निर्णय किया गया था। इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरूप 3500 शहरी परिवार तथा 9860 ग्रामीण परिवार प्रभावित होंगे जिनमें से 5550 ग्रामीण परिवार केवल आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। प्रथम चरण में, 1924 पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों में से 1880 का पहले ही पुनर्वास किया जा चुका है।